PM Gati shakti summit related Press clippings and feedback

12.04.2023

PIB Varanasi

Press Information Bureau, Varanasi	
Title of the report	
Name of the publication	Hindustan
Page No.	
Date	12.04.2023
Language of publication	Hindi
Place of Publication	Varanasi

epaper
हिन्दुस्तान
Share Copy url Save Font Size D'load Image Image Text Listen

मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर

पीएम गतिशक्ति

- उद्योग मंत्रालय की विशेष सचिव ने कहा, बढ़ेगा पर्यटन-व्यापार
- सांस्कृतिक संकुल में नेशनल मास्टर प्लान पर कार्यशाला शुरू

वाराणसी, संवाददाता। पूर्वी भारत में पूर्वांचल केंद्रित उद्योग, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों ने मंगलवार को बेहतर मल्टी मॉडल (जल, थल और नभ) कनेक्टिविटी पर जोर दिया। उद्योग मंत्रालय की विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स) सुमिता डावरा ने कहा कि सड़क, रेल और वायु परिवहन को आपस में जोड़कर बेहतर ट्रांसपोर्टेशन का प्रयास चल रहा है। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि लॉजिस्टिक की लागत घटेगी, उद्योग-व्यवसाय और पर्यटन की रफ्तार बढ़ेगी।

चौकाघाट स्थित गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में शुरू हुई पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान की दो दिवसीय पांचवीं क्षेत्रीय कार्यशाला में बिहार, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अधिकारियों ने मंथन किया। यूपी के प्रमुख सचिव (औद्योगिक विकास) अनिल सागर ने कहा कि सरकार उद्योग-धंधों के विस्तार के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर और परिवहन को बेहतर करने का प्रयास कर रही है। नीति आयोग के अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि गुजरात के 'पहुंच' पोर्टल पर स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों और गोवा में डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर की जियो मैपिंग हुई है।

दूसरे राज्यों को भी यह प्रयास करना चाहिए। कार्यशाला में इन्वेस्ट यूपी से अभिषेक प्रकाश, सड़क परिवहन मंत्रालय से एके पांडेय, पेट्रोलियम मंत्रालय से प्रकाश कोशी, बिजली मंत्रालय गणेश्वर राव, एनआईसीडीसी से अभिषेक चौधरी, दूरसंचार मंत्रालय के अवर सचिव नीरज कुमार, नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के पीवी तरुण साकेत ने आदि ने भी अनुभव साझा किए। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने विशेषज्ञों से परिवहन, लॉजिस्टिक, पीएम गतिशक्ति आदि विषयों पर सवाल-जवाब भी किए।

ग्रीनफील्ड से जुड़ रहे इकोनॉमिक जोन : उद्योग मंत्रालय की विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स) सुमिता डावरा ने देर शाम पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गोरखपुर-सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट से छह इकोनॉमिक जोन, छह एयरपोर्ट, दस प्रमुख रेलवे स्टेशन और जलमार्ग भी जुड़ रहे हैं।

बुधवार तक चलने वाली इस कार्यशाला में वर्ष-2047 को ध्यान में रखते हुए सुगम, समक्ष और आधुनिक परिवहन तंत्र विकसित करने के उपायों पर चर्चा होगी।

पीएम गतिशक्ति कार्यशाला का शुभारंभ करतीं उद्योग मंत्रालय की विशेष सचिव।

बहु आयामी परिवहन को रेलवे दे रहा बढ़ावा

पूर्वोत्तर रेलवे (गोरखपुर) की उप मुख्य परिचालन प्रबंधक शिल्पी कनौजिया ने कहा कि रेलवे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है। महराजगंज से नेपाल के सीमावर्ती स्थान घुघुली तक 52 किमी लम्बी लाइन बिछाई जा रही है। इस पर कुल आठ स्टेशन बनेंगे। इससे बिहार से आने वाली ट्रेन वाया नरकटियागंज भी गुजरेंगी। उससे गोरखपुर स्टेशन पर ऑपरेशनल लोड कम होगा।

25 वर्षों में दस हजार मिलियन एमटी ढुलाई

जलमार्ग मंत्रालय के डेवलपमेंट एडवाइजर एचएन अश्वथ ने कहा कि इनलैंड वाटरवेज बनाने में आने वाली अड़चनों को दूर किया जा रहा है। अगले 25 वर्षों में कार्गो से 10 हजार मिलियन मीट्रिक टन सामानों की ढुलाई का लक्ष्य रखा गया है। अर्बन वाटर ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए रोरो व अन्य माध्यमों को विकसित किया जा रहा है।

Press Information Bureau, Varanasi	
Title of the report	
Name of the publication	Dainik jagran
Page No.	
Date	12.04.2023
Language of publication	Hindi
Place of Publication	Varanasi

बुनियादी सुविधाओं के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जरूरी

जागरण संवाददाता, वाराणसी : किसी गांव या क्षेत्र की तस्वीर बदलनी हो या देश को 2048 तक विकसित राष्ट्र बनाना हो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) और स्टेट मास्टर प्लान (एसएमपी) का पूरा प्रयोग करना होगा। राज्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने में अधिक से अधिक एनएमपी और एसएमपी का प्रयोग करें। जियो टैग डेटा के विकास के लिए स्थानीय रिमोट सेंसिंग एजेंसियों, अंतरिक्ष एजेंसियों का लाभ उठाएं। यह अपील केंद्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) की विशेष सचिव सुमिता डावरा के हैं। वह वाराणसी में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) पर दो दिवसीय कार्यशाला का मंगलवार को शुभारंभ के बाद संबोधित कर रहीं थीं।

कार्यशाला को डीपीआइआइटी और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आयोजित किया है। इसमें छह राज्य भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने कई परियोजनाएं पीएम गतिशक्ति के माध्यम से तैयार की हैं जो जरूरी, ज्यादा लाभदायक होने के साथ ही मल्टी माडल लाजिस्टक्स कनेक्टिविटी को सुगम और सस्ता बना रही हैं। औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनिल सागर ने मीडिया को बताया कि यूपी ने पीएम गतिशक्ति का अलग ढंग से प्रयोग किया है। अपने सभी अनाज क्रय केंद्र, स्कूल व अस्पताल का डेटा अपडेट कर दिया है। देखा गया कि कहां इनकी आवश्यकता है। इस बार कुछ क्रय केंद्र पीएम गतिशक्ति के माध्यम से खोले गए। हरियाणा ने बताया उसने सभी राजस्व डाटा अपलोड कर दिया है। कार्यशाला में एसएमपी की आवश्यकता, डेटा गुणवत्ता प्रबंधन, क्लस्टर-आधारित क्षेत्र दृष्टिकोण, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए समग्र योजना दृष्टिकोण आदि मुख्य आकर्षण रहा।

सांस्कृतिक संकुल सभागार में आयोजित गतिशक्ति कार्यशाला के बारे में जानकारी देतीं विशेष सचिव श्रीमती सुमिता डावरा● जागरण

पद्मभूषण गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल सभागार में आयोजित गतिशक्ति कार्यशाला के दौरान बैठे अधिकारी● जागरण

महराजगंज में रेलवे लाइन कम करेगी गोरखपुर का भार

गतिशक्ति योजना से महराजगंज में रेलवे लाइन डाली जाएगी। इसके लिए आनंद नगर से गूगली को महराजगंज से होते हुए जोड़ा जाएगा। 53 किलोमीटर रेलमार्ग से महाराजगंज में रेलवे लाइन की कमी तो दूर होगी। साथ ही गोरखपुर पर ट्रेनों के दबाव को कम किया जा सकेगा। ट्रेन वाल्मीकी नगर से महराजगंज होते हुए गोंडा चली जाएगी। इससे सिमेंट, उर्वरक, कोयला, अनाज ढुलाई में आसानी होगी।

120 अधिकारियों ने भाग लिया: पीएम गतिशक्ति कार्यशाला में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अधिकारी भाग ले रहे हैं। इसमें रेलवे, डीपीआइआइटी, नीति आयोग, आइआइटीडी, एनआइसीडीसी, बीआइएसएजी-एन के अलावा विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित अधिकारी हैं।

इंडो नेपाल-हल्दिया ग्रीनफील्ड कोरिडोर से 18 प्रतिशत कम होगी दूरी: पीएम गतिशक्ति के माध्यम से तैयार इंडो नेपाल बार्डर-हल्दिया ग्रीनफील्ड 673 किलोमीटर कारिडोर बनेगा। इसके बनने से 18 प्रतिशत दूरी घट जाएगी। साथ ही यात्रा में लगने वाला 18 घंटे समय कम होकर सात घंटे रह जाएगा।

क्या है पीएम गतिशक्ति

पीएम नरेन्द्र मोदी ने अक्टूबर 2021 में पीएम गतिशक्ति योजना को लांच किया। इसका उद्देश्य लाजिस्टिक पर आने वाले खर्च को कम करना, कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना और सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में लगने वाले समय को कम करना है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करने वाले सभी विभागों सड़क, रेल, हवाई अड्डा, बंदरगाहों को जोड़ा गया है।

Press Information Bureau, Varanasi	
Title of the report	
Name of the publication	Amar ujala
Page No.	
Date	12.04.2023
Language of publication	Hindi
Place of Publication	Varanasi

अटकीं योजनाओं को मिलेगी गति

पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर आधारित दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन

संवाद न्यूज एजेंसी

वाराणसी। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के जरिये देश भर की अटकीं योजनाओं को गति देने का अभियान मंगलवार को शुरू किया गया। चौकाघाट स्थित सांस्कृतिक संकुल में वाणिज्य मंत्रालय की ओर से पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर आधारित दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन हुआ। इसमें वक्ताओं ने कहा कि विकसित देशों की कतार में भारत को खड़ा करने के लिए पीएम गति शक्ति योजना लाई गई है। इस योजना से सभी अटकीं योजनाओं को गति दी जाएगी। इसमें ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिये आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। इस संबंध में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया गया।

कार्यशाला में विशेष सचिव, लॉजिस्टिक्स सुमिता डावरा ने कहा कि पीएम गतिशक्ति एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। इसे देश में अगली पीढ़ी के लिए बुनियादी ढांचे की योजना बनाने और निर्माण के लिए लांच किया गया था, जिससे ईज ऑफ लिविंग के साथ-साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। कार्यशाला में डेटा गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) को तेजी से लागू करने के मुद्दों पर पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन दिया गया। पीएम गतिशक्ति के तहत डेटा लेयर्स गुणवत्ता सुधार योजना (क्यूआईपी), सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमजी) और यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी) का उपयोग कर लॉजिस्टिक सहूलियत के तकनीकी इंटरफेस के उपयोग की प्रगति निगरानी पर चर्चा की गई।

कार्यक्रम में एचएन अवस्थी ने पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग पर प्रेजेंटेशन दिया। बताया कि काशी से हल्दिया तक और बोगीबील तक सुविधाओं का विकास किया जा चुका है। इसके अलावा इसमें तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पीबी तरूण साकेत ने अक्षय ऊर्जा को नए युग की ऊर्जा बताया। इस मौके पर प्रकाश कोशी, गणेश्वर जे राव, अभिषेक चौधरी, अभिषेक अग्रवाल ने भी पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन दिया।

गति शक्ति कार्यशाला को संबोधित करते आरपी सिंह। संवाद

रेलवे ट्रैक से जुड़ेगा महाराजगंज

कार्यशाला में रेलवे के विकास मॉडल को प्रदर्शित करते हुए शिल्पी कन्नौजिया ने बताया कि पूर्वांचल में रेल विकास का नया पैमाना बनाया जाएगा। पहली बार महाराजगंज को रेल से जोड़ा जाएगा। पहले कोयला, सीमेंट जैसे सामान गोरखपुर से सड़क मार्ग से भेजा जाता था। रेल मार्ग से जुड़ जाने पर व्यापारी अपने उत्पाद सीधे महाराजगंज से मंगा सकेंगे। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज के रास्ते आनंद नगर और हुगली के बीच लगभग 53 किलोमीटर तक फैली नई ब्रॉड-गेज लाइन का का मॉडल पेश किया गया। यह ब्रॉड गेज गोरखपुर जंक्शन पर रुके बिना महाराजगंज होते हुए बाल्मीकि नगर से गोडा तक जाने वाली ट्रेनों का वैकल्पिक मार्ग होगा।

रोप-वे के निर्माण कार्य में आएगी तेजी

सड़क और हाईवे यातायात पर प्रस्तुतिकरण में आरपी सिंह ने कहा कि काशी में रोप-वे का काम तेजी से पूरा कराया जाएगा। बताया कि पहले विभागों की आपसी खींचतान और भूमि अभिग्रहण जैसी समस्याओं के चलते परियोजनाओं को पूरा करने में परेशानी होती थी। पीएम गतिशक्ति में सभी स्टेकहोल्डर एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। इससे परियोजनाओं में तेजी आएगी।

मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी से उत्पादन लागत कम होगी

प्रस्तावित गोरखपुर-सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड खरिखण (618 किमी) के लिए क्षेत्र में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाने और निर्माण लागत को कम करने के लिए उपयोगी पाया गया। इंडो-नेपाल बॉर्डर-हल्दिया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर (673 किलोमीटर), 14 जिलों में 30 आर्थिक नोड्स जैसे - पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली (बिहार), धनबाद (झारखंड), पुरुलिया और बांकुरा (पश्चिम बंगाल) में कनेक्टिविटी में सुधार करेगा।

कॉरिडोर से जुड़ेंगे 18 रेलवे स्टेशन व छह हवाई अड्डे

पूर्वोत्तर में विकास के लिए गोरखपुर को केंद्र में रखकर प्रस्तावित कॉरिडोर अठारह रेलवे स्टेशनों (जैसे, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि), छह हवाई अड्डे (पटना आदि) हल्दिया पोर्ट को जोड़ेंगे। एनएमपी पोर्टल के माध्यम से यह लंबाई में 18 प्रतिशत की कमी से यात्रा का समय 18 घंटे से घट कर सात घंटे हो जाएगा। इससे लागत में कमी आएगी और ईंधन की बचत होगी।

Press Information Bureau, Varanasi	
Title of the report	
Name of the publication	Amar ujala select
Page No.	
Date	12.04.2023
Language of publication	Hindi
Place of Publication	Varanasi

अटकी योजनाओं को मिलेगी गति

पीएम गति शक्ति के राष्ट्रीय मास्टर प्लान के स्टेक होल्डर्स ने दी कार्यशाला में प्रस्तुति

वाराणसी। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के जरिये देश भर की अटकी योजनाओं को गति देने का अभियान मंगलवार को शुरू किया गया। चौकाघाट स्थित सांस्कृतिक संकुल में वाणिज्य मंत्रालय की ओर से पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर आधारित दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन हुआ। इसमें वक्ताओं ने कहा कि विकसित देशों की कतार में भारत को खड़ा करने के लिए पीएम गति शक्ति योजना लाई गई है। इस योजना से सभी अटकी योजनाओं को गति दी जाएगी। इसमें ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिये आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। इस संबंध में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया गया।

कार्यशाला में विशेष सचिव, लॉजिस्टिक्स सुमिता डावरा ने कहा कि पीएम गतिशक्ति एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। इसे देश में अगली पीढ़ी के लिए बुनियादी ढांचे की योजना बनाने और निर्माण के लिए लांच किया गया था, जिससे ईज ऑफ लिविंग के साथ-साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। कार्यशाला में डेटा गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय

सांस्कृतिक संकुल में वाणिज्य मंत्रालय की ओर से पूर्वोत्तर के विकास के लिए आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करतीं सुमिता डावरा।

मास्टर प्लान (एनएमपी) को तेजी से लागू करने के मुद्दों पर पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन दिया गया। पीएम गतिशक्ति के तहत डेटा लेयर्स गुणवत्ता सुधार योजना (क्यूआईपी), सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमजी) और यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी) का उपयोग कर लॉजिस्टिक सहूलियत के तकनीकी इंटरफेस के उपयोग की प्रगति निगरानी पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में एचएन अवस्थी ने पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग पर प्रेजेंटेशन दिया। बताया कि काशी से हल्दिया तक और बोगीबील तक सुविधाओं का विकास किया जा चुका है। इसके अलावा इसमें तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पीवी तरूण साकेत ने अक्षय ऊर्जा को नए युग की ऊर्जा बताया। इस मौके पर प्रकाश कोशी, गणेश्वर जे राव, अभिषेक चौधरी, अभिषेक अग्रवाल ने भी पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन दिया।

विशेषज्ञों ने किया दावा, इज आफ लिविंग व डूइंग से आर्थिक गतिविधियां होंगी तेज

रोप-वे के निर्माण कार्य में आएगी तेजी

सड़क और हाईवे यातायात पर प्रस्तुतिकरण में आरपी सिंह ने कहा कि काशी में रोप-वे का काम तेजी से पूरा कराया जाएगा। बताया कि पहले विभागों की आपसी खींचतान और भूमि अधिग्रहण जैसी समस्याओं के चलते परियोजनाओं को पूरा करने में परेशानी होती थी। पीएम गतिशक्ति में सभी स्टेकहोल्डर एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। इससे परियोजनाओं में तेजी आएगी।

रेलवे टैक से जुड़ेगा महाराजगंज: कार्यशाला में रेलवे के विकास मॉडल को प्रदर्शित करते हुए शिल्पी कन्नोजिया ने बताया कि पूर्वांचल में रेल विकास का नया पैमाना बनाया जाएगा। पहली बार महराजगंज को रेल से जोड़ा जाएगा। पहले कोयला, सीमेंट जैसे सामान गोरखपुर से सड़क मार्ग से भेजा जाता था। रेल मार्ग से जुड़ जाने पर व्यापारी अपने उत्पाद सीधे महाराजगंज से मंगा सकेंगे। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज के रास्ते आनंद नगर और हुगली के बीच लगभग 53 किलोमीटर तक फैली नई ब्रॉड-गेज लाइन का का मॉडल पेश किया गया। यह ब्रॉड गेज गोरखपुर जंक्शन पर रुके बिना महराजगंज होते हुए बाल्मीकि नगर से गोंडा तक जाने वाली ट्रेनों का वैकल्पिक मार्ग होगा।

मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी से उत्पादन लागत कम होगी: प्रस्तावित गोरखपुर-सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड संरेखण (618 किमी) के लिए क्षेत्र में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाने और निर्माण लागत को कम करने के लिए उपयोगी पाया गया। इंडो-नेपाल बॉर्डर-हल्दिया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर (673 किलोमीटर), 14 जिलों में 30 आर्थिक नोड्स जैसे - पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली (बिहार), धनबाद (झारखंड), पुरुलिया और बांकुरा (पश्चिम बंगाल) में कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। **कॉरिडोर से जुड़ेंगे 18 रेलवे स्टेशन व छह हवाई अड्डे** पूर्वोत्तर में विकास के लिए गोरखपुर को केंद्र में रखकर प्रस्तावित कॉरिडोर अठारह रेलवे स्टेशनों (जैसे, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि), छह हवाई अड्डे (पटना आदि) हल्दिया पोर्ट को जोड़ेंगे।

Press Information Bureau, Varanasi	
Title of the report	
Name of the publication	Hindustan times
Page No.	
Date	12.04.2023
Language of publication	English
Place of Publication	Varanasi

Hindustan 2

{ PM GATISHAKTI WORKSHOP }

States/UTs urged to focus on progress of economic centres

HT Correspondent
letters@htlive.com

VARANASI: Sumita Dawra, special secretary, logistics, department for promotion of industry and internal trade (DPIIT), Union commerce and industry ministry, has urged states and Union Territories (UTs) to use National Master Plan (NMP)/ State Master Plan (SMP) for planning all upcoming infrastructure projects and improve data mapping and authenticity of data on the SMP.

She was addressing a two-day regional workshop of the fifth regional meet of PM GatiShakti National Master Plan (NMP) being organised by DPIIT that commenced in Varanasi on Tuesday.

The objective of the workshop is to promote wider adoption of PM GatiShakti for holistic planning, bringing more vigour and building synergy with all the stakeholders of the NMP.

Six states, including Uttar Pradesh, Haryana, Jharkhand, Bihar, Odisha and West Bengal, are participating in the workshop. They presented their experiences and successful adoption of PM GatiShakti in project planning.

Dawra appealed to the states to focus on development of economic centres through appropriate infrastructure and logistics development, identify critical infrastructure gaps and ensure they are taken up for connectivity projects.

PM GatiShakti is a transformative approach which was launched on October 13, 2021 by PM Narendra Modi for planning and building next generation infrastructure in the country, thereby promoting multimodal logistics connectivity to improve both ease of living as well as ease of doing business.

Principal secretary, infrastructure and industrial development department (IIDD), U.P., Anil Sagar also addressed the participants. Over 120 participants, including senior government officials related to infrastructure, the economic and social sectors from different central ministries, state departments, NITI Aayog etc are participating in the workshop.

Unified Logistics Interface Platform (ULIP) was the highlight of the first day of the programme. Through the regional workshop, six participating states showcased the good work already done and how these efforts could be further reinforced.

How NMP helped U.P.

Uttar Pradesh showcased how the government has integrated its education portal–PAHUNCH with the NMP, to use this technology backed platform for decision making pertaining to site suitability of schools, connectivity planning to schools, hospitals, distance of wheat purchase centres from wheat production areas etc. The state government is using PM GatiShakti approach for all key infrastructure projects and for city logistics.

Likewise, mapping and planning of projects under Kalinga Nagar National Investment Zone is being done using PM GatiShakti NMP in Odisha. In West Bengal, PM GatiShakti NMP is being used for planning of industrial and economic corridors. In Jharkhand, three projects have been planned and mapped on the PM Gatishakti SMP portal.

In Haryana, six mobile applications have been developed for mapping street infrastructure for 5G rollout, transmissions lines and anganwadi centres. Bihar is linking skill mapping of work force with its districts to identify the requirements of the work force.

Press Information Bureau, Varanasi	
Title of the report	
Name of the publication	times of india
Page No.	
Date	12.04.2023
Language of publication	English
Place of Publication	Varanasi

PM GatiShakti NMP workshop of 6 states for holistic planning begins

Infra Planning For Multimodal Connectivity Discussed On Inaugural Day

Times News Network

Varanasi: The two-day regional workshop on the PM GatiShakti National Master Plan (NMP), being organised by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce & Industry, government of India, commenced at Girija Devi Cultural Complex auditorium here on Tuesday with an objective to promote its wider adoption for holistic planning, bring more vigour and build synergy with all the stakeholders.

Regarding Tuesday's activities, special secretary, DPIIT Sumita Dawra and Anil Sagar Principal Secretary, Infrastructure and Industrial Development Department (IIDD), UP government said, "The inaugural day of the workshop featured discussions on infrastructure planning for multimodal connectivity using already executed or under progress cases from ministries and departments at the Centre and state levels."

Officials addressing the workshop of the fifth regional PM Gatishakti NMP meet in Varanasi on Tuesday

Presentations on the adoption of the PM GatiShakti with a holistic approach and demonstrations of best practices by states also featured in the workshop. Deliberations on requirements for State Master Planning, with special attention on data quality management, cluster-based area approach to develop economic centres in the states/UTs through adequate multimodal connectivity, holistic planning approach for the upcoming infrastructure projects, use of technology for logistics efficiency through Unified Logistics Interface Platform (ULIP), remained the main highlights of the first day of the programme.

Officials from the Central ministries and states shared their experiences including the proposed Gorakhpur–Siliguri Greenfield alignment, Indo-Nepal Border-Haldia greenfield corridor to show how they will help to improve connectivity to economic nodes, railway stations, airports, waterways and also reduction in the length of the alignment to reduce travel time saving fuel and others.

Dawra said that these improvements bring ease of logistics. "It brings down logistics cost and our standard becomes globally comparable. Our manufacturing becomes globally competitive. This is very important for make India to bring down the logistic cost," she said.

Other ministries, NITI Aayog and participating states including UP, Bihar, Haryana, West Bengal, Odisha and Jharkhand also shared their experiences.

Dawra said PM GatiShakti is a transformative approach which was launched in October 2021 by the Prime Minister Narendra Modi for planning and building next generation infrastructure in the country, thereby promoting multimodal logistics connectivity to improve both 'Ease of Living' as well as 'Ease of Doing Business.'

Over 120 participants including senior government officials related to infrastructure, the economic and social sectors from different Central ministries, state departments, BISAG-N, NITI Aayog, and NICDC are participating in the workshop. She said that since the launch of the PM GatiShakti NMP, the concerned ministries and all the states/UTs are being boarded on mission-mode. Institutional frameworks have been set up, GIS-based individual portals and customised decision-making tools have been developed, along with in-house capacities to adopt PM GatiShakti principles in project planning and implementation. Presently, GIS data based NMP is being extensively used for project planning and implementation by ministries at central level and most states.

She said the area approach concept was also discussed with a view to promote comprehensive, holistic, and integrated infrastructure development across the country, along with bridging critical infrastructure gaps, and addressing relative infrastructure deficit, across various economic zones/ industrial parks, etc.

Press Information Bureau, Varanasi	
Title of the report	
Name of the publication	The pioneer
Page No.	
Date	12.04.2023
Language of publication	English
Place of Publication	Varanasi

Regional PM GatiShakti NMP focuses on infra planning

PIONEER NEWS SERVICE ■ VARANASI

The two-day regional workshop on PM GatiShakti National Master Plan (NMP), being organised by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce & Industry, Government of India, began here on Tuesday with the objective to promote wider adoption of PM GatiShakti for holistic planning, bring more vigor and build synergy with all the stakeholders. PM GatiShakti is a transformative approach which was launched on October 13 in 2021 by Prime Minister Narendra Modi for planning and building next generation infrastructure in the country, thereby promoting multimodal logistics connectivity to improve both ease of living as well as ease of doing business.

The inaugural day of the workshop featured discussions on infrastructure planning for multimodal connectivity with use cases from ministries and departments at the centre and state levels.

The workshop was addressed by Sumita Dawra, Special Secretary, DPIIT and Anil Sagar, Principal Secretary, Infrastructure and Industrial Development Department (IIDD), Government of UP. Over 120 participants including senior government officials related to infrastructure, the economic and social sectors from different central ministries, state departments, BISAG-N, NITI Aayog, and NICDC are participating in the workshop to share their experiences, best practices, and vision. Senior officers from states including Uttar Pradesh, Haryana, Jharkhand, Bihar, Odisha, and West Bengal, are also participating in the workshop, and presented their experiences and successful adoption of PM GatiShakti in project planning.

Special Secretary of DPIIT Sumita Dawra inaugurating Regional PM GatiShakti NMP in Varanasi on Tuesday.

The day's workshop concluded with the remarks from Sumita Dawra requesting the states/UTs to use NMP/ SMP for planning all upcoming infrastructure projects; improve data mapping and authenticity of data on the data layers mapped on SMP; focus on development of economic centres through appropriate infrastructure and logistics development; identify critical infrastructure gaps and ensure they are taken up for connectivity projects and leverage local remote sensing agencies / space agencies for development of geo-tagged data.

She said that area approach to be prioritised for socio-economic development for ensuring ease of living and ease of doing business.

The second day of the workshop will feature sessions on National Logistics Policy (NLP), and state logistics policies, and drawing an understanding for creating sustainable cities.

Presentations on the adoption of PM GatiShakti with a holistic approach and demonstrations of best practices by states also featured in the workshop on the first day. Deliberations on requirements for state master planning, with special attention on data quality management, cluster-based area approach to developing economic centres in the states/UTs through adequate multimodal connectivity, holistic planning approach for upcoming infrastructure projects, use of technology for logistics efficiency through Unified Logistics Interface Platform (ULIP), have been the main highlights of the day.

Since the launch of PM GatiShakti NMP, concerned ministries and all states/UTs have been on-boarded on mission-mode.

Institutional frameworks have been set up, GIS-based individual portals and customised decision-making tools have been developed, along with in-house capacities to adopt PM GatiShakti principles in project planning and implementation. Presently, GIS data based National Master Plan is being extensively used for project planning and implementation by ministries at central level and most states.

The feedback from the all five regional workshops conducted from February to April 2023, covering all 36 states and UTs of the country, has been very reassuring, as significant usage of the PM GatiShakti NMP and its principles has been observed from participating states and UTs. Workshops held so far were at Goa (20 Feb 2023), Kochi (9-10 March), Srinagar (17-18 March), Guwahati (24-25 March) and present at Varanasi (11-12 April).

Press Information Bureau, Varanasi	
Title of the report	
Name of the publication	Jansandesh times
Page No.	
Date	12.04.2023
Language of publication	Hindi
Place of Publication	Varanasi

परिवहन व्यवस्था हो मजबूत तो बढ़ेगा व्यापार

पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान कार्यशाला का दीप जलाकर उद्घाटन करते अतिथि

कार्यशाला

पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का संकुल में आयोजन

वाराणसी। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला चौकाघाट स्थित गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में मंगलवार से शुरू हुआ। विशेषज्ञों ने कहा कि जल, थल और नभ परिवहन की स्थिति अच्छी होगी तो व्यवसाय और पर्यटन की रफ्तार बढ़ेगी।

केंद्रीय उद्योग मंत्रालय की स्पेशल सेक्रेटरी समिति की तरफ से आयोजित कार्यशाला में विशेषज्ञों ने कहा कि इसमें मल्टी मॉडल एप्रोच सिस्टम को बढ़ावा देना कारगर साबित होगा। आउटरीच एरिया को रेल, सड़क और जलमार्ग के माध्यम से जोड़ने, संचार व्यवस्था को बेहतर करने, वाटरवेज बनाने में आने वाली अड़चनों को दूर करने, एनएमपी पोर्टल की सहायता लेने, अर्बन वाटर ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने, ऊर्जा के नवीन तरीको को अपनाने और लॉजिस्टिक क्षमता बढ़ाने को पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। प्रथम सत्र में सड़क परिवहन, रेल, दूरसंचार, जलमार्ग, ऊर्जा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने विचार व्यक्त किये। इस दौरान मौजूद विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने विशेषज्ञों से परिवहन, लॉजिस्टिक, पीएम गति शक्ति समेत अन्य विषयों पर सवाल भी पूछे। डीपीआईआईटी में विशेष सचिव सुमिता डावरा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपील की कि वे सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए एनएमपी/ एसएमपी का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एरिया एप्रोच को प्राथमिकता दी जाएगी। बुनियादी ढांचा व औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडीडी) के प्रधान सचिव अनिल सागर ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। कार्यशाला के पहले दिन केंद्र और राज्य स्तर पर मंत्रालयों और विभागों से उपयोग के मामलों के साथ मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचा योजना पर चर्चा हुई। कार्यशाला में बिहार, हरियाणा, झारखंड, ओडीशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आए अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

निर्माणाधीन परियोजनाएं जल्द पूरा कर शुरू करें परिचालन

वाराणसी। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने मंगलवार को रुर्बन मिशन तथा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत संचित परियोजनाओं की समीक्षा की। रुर्बन मिशन के तहत निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम पिपरी व ग्राम पंचायत गरथौली में जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं पानी हाउस व मंडी को तत्काल पूर्ण कराकर इसका परिचालन कराने का निर्देश दिया। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत ग्राम पंचायत पुरे व कुरहुआ में तालाब निर्माण, कंपोस्ट पिट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, डस्टबिन, शेल्टर, आंगनवाड़ी केंद्र भवन, आंतरिक सड़क मार्ग निर्माण कार्य को भी शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया।

Press Information Bureau, Varanasi	
Title of the report	
Name of the publication	Rashtriya sahara
Page No.	
Date	12.04.2023
Language of publication	Hindi
Place of Publication	Varanasi

सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एरिया एप्रोच को दी जाएगी प्राथमिकता : सुमिता

पीएम गतिशक्ति एनएमपी पर दो दिनी पांचवीं क्षेत्रीय कार्यशाला शुरू

वाराणसी (एसएनबी)। देश की सांस्कृतिक राजधानी के तौर विख्यात वाराणसी में मंगलवार को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) पर दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों संग केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। केन्द्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यशाला का मकसद पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के सभी स्टेक होल्डर्स के बीच तालमेल बनाना और जोश पैदा करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गतिशक्ति को देश में अगली पीढ़ी के लिये बुनियादी ढांचे की योजना बनाने के उद्देश्य से लांच किया था। इससे ईज ऑफ लिविंग के साथ-साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन मिला है।

डीपीआईआईटी में विशेष सचिव सुमिता डावरा और बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडीडी) के प्रधान सचिव अनिल सागर ने कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर बीआईएसएजी-एन, नीति आयोग और एनआईसीडीसी के अलावा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों समेत 120 से अधिक प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किये। सुमिता डावरा ने कहा कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एरिया एप्रोच को प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यशाला के पहले दिन केंद्र और राज्य स्तर पर मंत्रालयों और विभागों में उपयोग के मामलों के साथ मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचा योजना पर चर्चा हुई।

राज्य मास्टर प्लानिंग की आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श, डेटा गुणवत्ता प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के साथ, पर्याप्त मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक केंद्रों के विकास के लिए क्लस्टर-आधारित क्षेत्र दृष्टिकोण, आगामी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए समग्र योजना दृष्टिकोण, लॉजिस्टिक दक्षता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) कार्यक्रम के पहले दिन का मुख्य आकर्षण रहा।

देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए फरवरी से अप्रैल (इसी माह) तक आयोजित सभी पांच क्षेत्रीय कार्यशालायें अब तक बहुत आश्वस्त करने वाली रही है। अब तक गोवा (20 फरवरी 2023), कोच्चि (9-10 मार्च 2023), श्रीनगर (17-18 मार्च 2023), गुवाहाटी (24-25 मार्च 2023) और वर्तमान में वाराणसी (11-12 अप्रैल) में कार्यशालायें आयोजित की गयी हैं। इस दौरान क्षेत्रीय दृष्टिकोण अवधारणा पर भी चर्चा की गई। देश भर में व्यापक, समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के अंतराल को पाटने और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों आदि में अपेक्षित बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए पीएम गतिशक्ति एरिया एप्रोच को अपनाया जा रहा है। देश भर में 100 स्थानों/आर्थिक नोड्स का विकास करना, एरिया एप्रोच का विजन अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से एक तर्कसंगत भौगोलिक स्थिति के भीतर एक स्थायी तरीके से सामाजिक-आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। विभिन्न आर्थिक नोड्स के आसपास 150-200 वर्ग किमी क्षेत्रफल वाले सामरिक स्थानों की पहचान बुनियादी ढांचे को गहन करने के साथ मौजूदा कनेक्टिविटी को बढ़ायेगी। इसके तहत चिन्हित क्षेत्रों के व्यापक और समग्र विकास के लिए बुनियादी ढांचे की कमी और रसद सुविधाओं की जरूरतों की पहचान करने में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यशाला के दूसरे दिन राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और राज्य लॉजिस्टिक नीतियों पर सत्र होंगे।

Press Information Bureau, Varanasi	
Title of the report	
Name of the publication	Dainik aaj
Page No.	
Date	12.04.2023
Language of publication	Hindi
Place of Publication	Varanasi

सामाजिक-आर्थिक विकासके लिए एरिया एप्रोच को प्राथमिकता देनेपर बल

वाराणसी में शुरू हुई पीएम गतिशक्ति एनएमपी पर पांचवीं क्षेत्रीय कार्यशाला

देश की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर विख्यात वाराणसी में मंगलवारको चौकाघाट स्थित सांस्कृतिक संकुल में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों के अलावा केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। केन्द्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का मकसद पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के सभी स्टेक होल्डर्स के बीच तालमेल बनाना और जोश पैदा करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13 अक्तूबर 2021 को पीएम गतिशक्ति को देश में अगली पीढ़ी के लिये बुनियादी ढांचे की योजना बनाने के उद्देश्य से लांच किया था। इससे ईज आफ लिविंग के साथ-साथ ईज आफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए मल्टीमाडल लाजिस्टिक्स कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन मिला है।

उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए डीपीआईआईटी की विशेष सचिव सुमिता डावरा ने सभी बुनियादी ढांचा के परियोजनाओं को योजना बनाने के लिए एनएमपी तथा एसएमपी का उपयोग करने की राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से अपील की। साथ ही एसएमपी के डेटा लेयर्स पर डेटा मैपिंग और डेटा की प्रमाणिकता में सुधार करें। उन्होंने उपयुक्त अवसंरचना और रसद विकास के माध्यम से आर्थिक केन्द्रों के विकास पर ध्यान देने की भी बात कही। उन्होंने जियो-टैग डेटा के विकास के लिए स्पेशियल रिमोट सेंसिंग एजेंसियों तथा आंतरिक एजेंसियों का लाभ उठाने पर जोर दिया। लब्बोलुआब यह रहा कि ईज आफ लिविंग और ईज आफ डूइंग बिजनेस दोनों को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एरिया एप्रोच को प्राथमिकता देने पर जोर रहा। कार्यशाला के पहले दिन केन्द्र और राज्यस्तर पर मंत्रालयों और विभागों से उपयोग मामलों के साथ मल्टीमाडल कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचा योजना पर चर्चा हुई। पीएम गतिशक्ति को अपनाने पर समग्र दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुतियां दी गयी। इसके अलावा राज्य मास्टर प्लानिंग की आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श, डेटा गुणवत्ता प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के साथ, पर्याप्त मल्टीमाडल कनेक्टिविटी के माध्यम से राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में आर्थिक केन्द्रों के विकास के लिए कलस्टर आधारित क्षेत्र दृष्टिकोण, आगामी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए समग्र योजना दृष्टिकोण, लाजिस्टिक दक्षता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, यूनिफाइड इंटरफेस प्लेटफार्म (यूलिप) कार्यक्रम के पहले दिन का मुख्य आकर्षण रहा। सत्र में बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडी) के प्रधान सचिव अनिल सागर के अलावा बीआईएसएजीएन, नीति आयोग, एनआईसीडीएस के साथ-साथ केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों समेत १२० से अधिक प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किये।

इज आफ लिविंग के साथ ईज आफ डूइंग बिजनेस में होगा सुधार

उद्योग और आन्तरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की विशेष सचिव सुमिता डावरा ने कहा कि पीएम गतिशक्ति योजना के तहत हो रहे कार्यों से बिजनेस में सुधार हो रहा है। मल्टीमाडल कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन मिला है। सुमिता डावरा मंगलवार को चौकाघाट स्थित सांस्कृतिक संकुल में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि जल थल एवं रेल मार्गों के जुड़ने से क्षेत्रों में तेजी से आर्थिक विकास हो रहा है। इज आफ लिविंग एवं इज आफ डूइंग बिजनेस दोनों को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एरिया एप्रोच को प्राथमिकता दी जा रही है। पर्याप्त मल्टीमाडल कनेक्टिविटी के माध्यम से राज्यों में आर्थिक विकास के केन्द्र बन रहे हैं।

Press Information Bureau, Varanasi	
Title of the report	
Name of the publication	Gyanshikha times
Page No.	
Date	12.04.2023
Language of publication	Hindi
Place of Publication	Varanasi

ज्ञानशिखा —8

पीएम गतिशक्ति एनएमपी पर पांचवीं क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित

वाराणसी । केन्द्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला मंगलवार को वाराणसी में शुरू हुई। कार्यशाला का मकसद पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के सभी स्टेक होल्डर्स के बीच तालमेल बनाना और जोश पैदा करना है। देश में अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे की योजना बनाने और निर्माण के लिए पीएम गतिशक्ति को प्रधानमंत्री ने 13 अक्टूबर, 2021 को लॉन्च किया था जिससे ईज ऑफ लिविंग के साथ-साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन मिला।

? कार्यशाला का पहला दिन पीएम गतिशक्ति एनएमपी अपनाने पर केंद्रित था। डीपीआईआईटी में विशेष सचिव श्रीमती सुमिता डावरा और बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडीडी) के प्रधान सचिव श्री अनिल सागर ने कार्यशाला को संबोधित किया। इस अवसर पर बीआईएसएजी-एन, नीति आयोग और एनआईसीडीसी के अलावा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों समेत 120 से अधिक प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किये। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यशाला में भाग ले रहे हैं।सुश्री सुमिता डावरा ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से अपील की कि वे सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए एनएमपी/एसएमपी का उपयोग करें। एसएमपी पर मैप की गई डेटा लेयर्स पर डेटा मैपिंग और डेटा की प्रामाणिकता में सुधार करें। उपयुक्त अवसंरचना और रसद विकास के माध्यम से आर्थिक केंद्रों के विकास पर ध्यान दें। महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतरालों की पहचान करने के साथ यह सुनिश्चित करें कि उन्हें कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए लिया गया है। जियो-टैग डेटा के विकास के लिए स्थानीय रिमोट सेंसिंग एजेंसियों/अंतरिक्ष एजेंसियों का लाभ उठाएं। ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एरिया एप्रोच को प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यशाला के पहले दिन केंद्र और राज्य स्तर पर मंत्रालयों और विभागों से उपयोग के मामलों के साथ मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचा योजना पर चर्चा हुई। पीएम गतिशक्ति को अपनाने पर समग्र दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुतियां दी गयी और राज्यों ने सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन किया। राज्य मास्टर प्लानिंग की आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श, डेटा गुणवत्ता प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के साथ, पर्याप्त मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक केंद्रों के विकास के लिए क्लस्टर-आधारित क्षेत्र दृष्टिकोण, आगामी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए समग्र योजना दृष्टिकोण, लॉजिस्टिक दक्षता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) कार्यक्रम के पहले दिन का मुख्य आकर्षण रहा। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के लॉन्च के बाद से संबंधित मंत्रालयों और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मिशन-मोड में शामिल कर लिया गया है। परियोजना योजना और कार्यान्वयन में पीएम गतिशक्ति सिद्धांतों को अपनाने के लिए आंतरिक क्षमताओं के साथ-साथ संस्थागत ढांचे की स्थापना की गई है। जीआईएस-आधारित व्यक्तिगत पोर्टल और अनुकूलित निर्णय लेने वाले उपकरण विकसित किए गए हैं। वर्तमान में केंद्रीय स्तर और अधिकांश राज्यों में मंत्रालयों द्वारा परियोजना नियोजन और कार्यान्वयन के लिए जीआईएस डेटा आधारित राष्ट्रीय मास्टर प्लान का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। ? देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए फरवरी से अप्रैल 2023 तक आयोजित सभी पांच क्षेत्रीय कार्यशालायें बहुत आश्वस्त करने वाली रही है।

Press Information Bureau, Varanasi	
Title of the report	
Name of the publication	Dainik manyavar
Page No.	
Date	12.04.2023
Language of publication	Hindi
Place of Publication	Varanasi

वाराणसी में शुरू हुयी पीएम गतिशक्ति एनएमपी पर पांचवीं क्षेत्रीय कार्यशाला

दैनिक मान्यवर

वाराणसी। देश की सांस्कृतिक राजधानी के तौर विख्यात वाराणसी में मंगलवार को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों के अलावा केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

केन्द्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यशाला का मकसद पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एमएमपी) के सभी स्टेक होल्डर्स के बीच तालमेल बनाना और जोश पैदा करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गतिशक्ति को देश में अगली पीढ़ी के लिये बुनियादी ढांचे की योजना बनाने के उद्देश्य से लांच किया था। इससे ईज ऑफ लिविंग के साथ-

साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन मिला है।

डीपीआईआईटी में विशेष सचिव श्रीमती सुमिता डावरा और बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडीडी) के प्रधान सचिव श्री अनिल सागर ने कार्यशाला के उदघाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर बीआईएसएजी-एन, नीति आयोग और एनआईसीडीसी के अलावा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों समेत 120 से अधिक प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किये। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। सुश्री सुमिता डावरा ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से अपील की कि वे सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए एनएमपी/एसएमपी का उपयोग करें। एसएमपी पर मैप की गई डेटा लेयर्स पर डेटा मैपिंग और डेटा की प्रामाणिकता में सुधार करें। उपयुक्त अवसंरचना और रसद विकास के माध्यम से आर्थिक केंद्रों के विकास पर ध्यान दें। महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतरालों की पहचान करने के साथ यह सुनिश्चित करें कि उन्हें कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए लिया गया है। जियो-टैग डेटा के विकास के लिए स्थानीय रिमोट सेंसिंग एजेंसियों/अंतरिक्ष एजेंसियों का लाभ उठाएं।उन्होने कहा कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एरिया एप्रोच को प्राथमिकता दी जाएगी।

कार्यशाला के पहले दिन केंद्र और राज्य स्तर पर मंत्रालयों और विभागों से उपयोग के मामलों के साथ मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचा योजना पर चर्चा हुई। पीएम गतिशक्ति को अपनाने पर समग्र दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुतियां दी गयी। राज्य मास्टर प्लानिंग की आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श, डेटा गुणवत्ता प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के साथ, पर्याप्त मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक केंद्रों के विकास के लिए क्लस्टर-आधारित क्षेत्र दृष्टिकोण, आगामी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए समग्र योजना दृष्टिकोण, लॉजिस्टिक दक्षता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) कार्यक्रम के पहले दिन का मुख्य आकर्षण रहा। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के लॉन्च के बाद से संबंधित मंत्रालयों और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मिशन-मोड में शामिल कर लिया गया है। परियोजना योजना और कार्यान्वयन में पीएम गतिशक्ति सिद्धांतों को अपनाने के लिए आंतरिक क्षमताओं के साथ-साथ संस्थागत ढांचे की स्थापना की गई है। जीआईएस-आधारित व्यक्तिगत पोर्टल और अनुकूलित निर्णय लेने वाले उपकरण विकसित किए गए हैं।

Press Information Bureau, Varanasi	
Title of the report	
Name of the publication	Samachar dhara
Page No.	
Date	12.04.2023
Language of publication	Hindi
Place of Publication	Varanasi

वाराणसी में शुरू हुयी पीएम गतिशक्ति एनएमपी पर पांचवीं क्षेत्रीय कार्यशाला

वाराणसी। देश की सांस्कृतिक राजधानी के तौर विख्यात वाराणसी में मंगलवार को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों के अलावा केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

केन्द्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यशाला का मकसद पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के सभी स्टेक होल्डर्स के बीच तालमेल बनाना और जोश पैदा करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गतिशक्ति को देश में अगली पीढ़ी के लिये बुनियादी ढांचे की योजना बनाने के उद्देश्य से लांच किया था। इससे ईज ऑफ लिविंग के साथ-

साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन मिला है।

डीपीआईआईटी में विशेष सचिव श्रीमती सुमिता डावरा और बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडीडी) के प्रधान सचिव श्री अनिल सागर ने कार्यशाला के उदघाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर बीआईएसएजी-एन, नीति आयोग और एनआईसीडीसी के अलावा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों समेत 120 से अधिक प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किये।

उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। सुश्री सुमिता डावरा ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से अपील की कि वे सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए एनएमपी/एसएमपी का उपयोग करें। एसएमपी पर मैप की गई डेटा लेयर्स पर डेटा मैपिंग और डेटा की प्रामाणिकता में सुधार करें। उपयुक्त अवसंरचना और रसद विकास के माध्यम से आर्थिक केंद्रों के विकास पर ध्यान दें। महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतरालों की पहचान करने के साथ यह सुनिश्चित करें कि उन्हें कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए लिया गया है।

जियो-टैग डेटा के विकास के लिए स्थानीय रिमोट सेंसिंग एजेंसियों/ अंतरिक्ष एजेंसियों का लाभ उठाएं। उन्होने कहा कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एरिया एप्रोच को प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यशाला के पहले दिन केंद्र और राज्य स्तर पर मंत्रालयों और विभागों से उपयोग के मामलों के साथ मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचा योजना पर चर्चा हुई।

Press Information Bureau, Varanasi	
Title of the report	
Name of the publication	Perfect mission
Page No.	
Date	12.04.2023
Language of publication	Hindi
Place of Publication	Varanasi

पीएम गतिशक्ति पर पांचवीं क्षेत्रीय दो दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। केन्द्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार सम्वर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। इस दो दिवसीय कार्यशाला मे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल ने हिस्सा लिया।

इस कार्यशाला का मकसद पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के सभी स्टेक होल्डर्स के बीच तालमेल बनाना और जोश पैदा करना है। देश में अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे की योजना बनाने और निर्माण के लिए पीएम गतिशक्ति को प्रधानमंत्री ने 13 अक्टूबर 2021 को लांच किया था जिससे इज आफ लिविंग के साथ साथ इज आफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए मल्टीमाडल लाजिस्टिक

कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन मिला। कार्यशाला का पहला दिन पीएम गतिशक्ति नहीं अपनाने पर केंद्रित था। डीपीआईआईटी में विशेष सचिव श्रीमती सुमिता डावरा और बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास विभाग के प्रधान सचिव अनिल सागर ने कार्यशाला को संबोधित किया।

इस अवसर पर बीआईएसए- एन नीति आयोग और एनआईसीडीसी के अलावा विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों समेत 120 से अधिक प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए ।उत्तर प्रदेश, हरियाणा झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यशाला में भाग लिए हैं। सुमिता डावरा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपील की कि वे सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए एनएमपी/ एसएमपी का उपयोग करें। एसएमपी पर मैप की गई डाटा लेयर्स पर डाटा मैपिंग और डाटा की प्रामाणिकता में सुधार करें। उपयुक्त अवसंरचना और विकास के माध्यम से आर्थिक केंद्रों के विकास पर ध्यान दें। कार्यशाला के पहले दिन केंद्र और राज्य स्तर पर मंत्रालयों और विभागों से उपयोग के मामलों के साथ मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचा योजना पर चर्चा हुई। पीएम गतिशक्ति को अपनाने पर समग्र दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुतियां दी गई और राज्यों ने सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन भी किया। राज्य मास्टर प्लानिंग की आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श डाटा गुणवत्ता प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ पर्याप्त मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के माध्यम से राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक केंद्रों के विकास के लिए क्लस्टर आधारित क्षेत्र दृष्टिकोण, आगामी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए समग्र योजना दृष्टिकोण, लॉजिस्टिक दक्षता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफार्म पर चर्चा हुई।

Press Information Bureau, Varanasi	
Title of the report	
Name of the publication	Jagruk express
Page No.	
Date	12.04.2023
Language of publication	Hindi
Place of Publication	Varanasi

जाए। रोकने का सख्त आदेश दिया। सहायक समीक्षा अधिकारी

'पीएम गतिशक्ति' पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित

जिला संवाददाता

वाराणसी। केन्द्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला आज वाराणसी में शुरू हुई। कार्यशाला का मकसद पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के सभी स्टेक होल्डर्स के बीच तालमेल बनाना और जोश पैदा करना है। देश में अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे की योजना बनाने और निर्माण के लिए पीएम गतिशक्ति को प्रधानमंत्री ने 13 अक्टूबर, 2021 को लॉन्च किया था जिससे ईज ऑफ लिविंग के साथ-साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन मिला। कार्यशाला का पहला दिन पीएम गतिशक्ति एनएमपी अपनाने पर केंद्रित था। डीपीआईआईटी में

विशेष सचिव श्रीमती सुमिता डावरा और बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडीडी) के प्रधान सचिव श्री अनिल सागर ने कार्यशाला को संबोधित किया। इस अवसर पर बीआईएसएजी-एन, नीति आयोग और एनआईसीडीसी के अलावा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों समेत 120 से अधिक प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किये। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। सुमिता डावरा ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से अपील की कि वे सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए एनएमपी/एसएमपी का उपयोग करें। एसएमपी पर मैप की गई डेटा लेयर्स पर डेटा मैपिंग और डेटा की प्रामाणिकता में सुधार करें। उपयुक्त अवसंरचना और रसद विकास के माध्यम से आर्थिक केंद्रों के विकास पर ध्यान दें।

कार्यालय ग्राम पंचायत

वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वच्छ भारत मिशन

*****